

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2019/फाल्गुन 6, 1940

No. 01]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2019/ PHALGUNA 6, 1940

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 01(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना अफसरों के वेतन नियमों, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों को सेना अफसर वेतन (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे।
- 2. सेना अफसर वेतन नियमावली, 2017 में, नियम 12 के खंड (ii) में शब्द "उनका मूल वेतन और उक्त प्रैक्टिस बंदी भत्ता का योग" के स्थान पर शब्द "उनका प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित मूल वेतन और मिलिट्री सेवा वेतन का योग" माना जाएगा।

[सं. 1(8)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) खंड-II-1] एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है। इसके तहत भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन के लिए पात्र है। तदनुसार, इन नियमों को 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1254 GI/2019 (1)

टिप्पण : सेना अफसर वेतन नियमावली, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.12(अ), दिनांक 03 मई, 2017 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF DEFENCE (Department of Defence) NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2019

- **S.R.O. 01(E).** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Army Officers Pay Rules, 2017, namely: -
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called Army Officers Pay (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.
- 2. In the Army Officers Pay Rules, 2017, in rule 12, in clause (ii), for the words "their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay", the words "their basic pay plus Non Practicing Allowance and Military Service Pay shall not exceed the average of basic pay" shall be substituted.

[No. 1(8)/2016-D (Pay/Services) Part-II-1] M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum: The Seventh Central Pay Commission has been implemented with effect from the 1stday of January, 2016. Likewise, the Defence Personnel of the Union of India are eligible for Seventh Central Pay revision with effect from the 1st day of January, 2016. Accordingly, these Rules have been given retrospective effect with effect from the 1st day of January, 2016. It is hereby, certified that by giving retrospective to these rules no one will be adversely affected.

Note: The Army Officers Pay Rules, 2017 were published in the Gazetteof India, Extraordinary, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O. 12(E), dated the 3rd May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 02(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुसेना अफसरों के वेतन नियमों, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों को वायुसेना अफसर वेतन (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा ।
 - (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे।
- 2. वायुसेना अफसर वेतन नियमावली, 2017 नियम 12, खंड (ii) में शब्द "उनका मूल वेतन और उक्त व्यवसाय निषेध भत्ता का योग" के स्थान पर शब्द "उनका व्यवसाय निषेध भत्ता सहित मूल वेतन और मिलिट्री सेवा वेतन का योग" माना जाएगा।

[सं. 1(8)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) खंड-II-2] एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है। इसके तहत भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन के लिए पात्र है। तदनुसार, इन नियमों को 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण: वायुसेना अफसर वेतन नियमावली, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 12(अ), दिनांक 03 मई, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2019

- **S.R.O. 02(E).** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Air Force Officers Pay Rules, 2017, namely: -
- (a) Short title and commencement. (1) These rules may be called Air Force Officers Pay (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.
- (b) In the Air Force Officers Pay Rules, 2017, in rule 12, in clause (ii), for the words "their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay", the words "their basic pay plus Non Practicing Allowance and Military Service Pay shall not exceed the average of basic pay" shall be substituted.

[No. 1 (8)/2016-D (Pay/Services) Part-II-2] M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum: The Seventh Central Pay Commission has been implemented with effect from the 1st day of January, 2016. Likewise, the Defence Personnel of the Union of India are eligible for Seventh Central Pay revision with effect from the 1st day of January, 2016. Accordingly, these Rules have been given retrospective effect with effect from the 1st day of January, 2016. It is hereby, certified that by giving retrospective to these rules no one will be adversely affected.

Note: The Air Force Officers Pay Rules, 2017 were published in the Gazetteof India, Extraordinary, Part II, section 4 vide notification number S.R.O. 13(E), dated the 3rd May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 03(अ).—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नौसेना अफसरों के वेतन विनियमों, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं,अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों को नौसेना अफसर वेतन (संशोधन) विनियमन, 2019कहा जाएगा ।
 - (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे।
- 2. (1) हिन्दी पाठ मे इसकी आवश्यकता नहीं है।
- (2) नौसेना अफसर वेतन विनियमन, 2017, विनियम 12, खंड (ii) में शब्द "मूल वेतन+ गैर-व्यवसाय भत्ता" के स्थान पर शब्द "मूल वेतन+ गैर-व्यवसाय भत्ता+मिलिट्टी सेवा वेतन" माना जाएगा।

[सं. 1(8)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) खंड-II-3] एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है । इसके तहत भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन के लिए पात्र है । तदनुसार, इन नियमों को 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है । एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण : नौसेना अफसर वेतन विनियमन, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 14(अ), दिनांक 03 मई, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2019

S.R.O. 03(E).— In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Navy Officers Pay Regulations, 2017, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These regulations may be called Navy Officers Pay (Amendment) Regulations, 2019.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.
- 2. In the Navy Officers Pay Regulations, 2017.
 - a) in regulation 5, in sub-regulation (2), in clause (iii), the word "only" occurring at the end shall be omitted;
 - b) in regulation 12, in clause (ii), for the words "their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay", the words "their basic pay plus Non Practicing Allowance and Military Service Pay shall not exceed the average of basic pay" shall be substituted.

[No. 1(8)/2016-D (Pay/Services) Part-II-3] M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum: The Seventh Central Pay Commission has been implemented with effect from the 1st day of January, 2016. Likewise, the Defence Personnel of the Union of India are eligible for Seventh Central Pay revision with effect from the 1st day of January, 2016. Accordingly, these Rules have been given retrospective effect with effect from the 1st day of January, 2016. It is hereby, certified that by giving retrospective to these rules no one will be adversely affected.

Note: The Navy Officers Pay Regulations, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O. 14(E), dated the 3rd May, 2017.